ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 434-438

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

भारतीय विदेश नीति में हिन्दुत्ववादी विचारधारा : एक विश्लेषण

विजय कुमार

सहायक आचार्य– रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), भारत

Received- 27.06.2020, Revised- 29.06.2020, Accepted - 30.06.2020 E-mail: - vijayanand8385@gmail.com

सारांश : ***"अंतर्राष्ट्रीय सम्बंध आपसी समझ और सहयोग पर आधारित हैं।"***

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

राष्ट्रीय लोकाचार पर आधारित भारत की विदेश नीति देश के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास एवं परिवर्तन की प्रक्रियाओं का समर्थन करती है। भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करना सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, देश की रणनीतिक स्वायत्ता को बनाए रखना तथा और अधिक उचित वैश्विकि व्यवस्था की दिशा में कार्य करना इस नीति के अभिन्न अंग हैं। भारत अपनी सीमाओं को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित रखने, अपने पड़ोसी देशों के साथ सम्बंधों का विस्तार करने, महाशक्तियों के साथ सौहाद्रपूर्ण एवं संतुलित रिश्ते कायम करने और विकासशील देशों के साथ परस्पर लाभदायक सहभागिता करने का इच्छुक है। भारत की विदेश नीति में सशक्त बहुपक्षीय आयाम भी हैं। जिसके तहत वह आज की चुनौतियों जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, चिरस्थायी विकास, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा और साइबर एवं अंतरक्षि सुरक्षा सम्बंधी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों तथा मंचों पर सहभागी देशों के साथ मिलकर कार्य कर रह है। परन्तु नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत की विदेश नीति की भारतीय विचारधारा में बड़े परिवर्तन की सम्भावनायें व्यक्त की गईं, साथ ही यह भी कहा गया कि मोदी की विदेश नीति अब हिन्दुवादी विचारधारा पर आधारित होगी। प्रस्तुत लेख विदेश नीति में विचारधारा के महत्व के साथ–साथ भारतीय विदेश नीति में हिन्दुवादी विचार के शामिल पर विचार प्रस्तुत करता है।

कुंजीभूत शब्द– राष्ट्रीय लोकाचार, आधारित, विकास, परिवर्तन, समर्थन, सुनिश्चित, सामाजिक,आर्थिक, विकास।

विदेश नीति में विचारधारा का उपयोग– कोई भी राष्ट्र अपनी विचारधारा के द्वारा ही अपने लोंगों के जीवन मूल्यों तथा नजरिये को व्यक्त करता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्बंधों में विचारधाराओं का सर्वाधिक महत्व होता है। इसी के माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को व्यक्त कर विश्व राजनीति तथा सम्बंधों का निर्धारण करता है। इसी के द्वारा उस राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मूल्यों का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है और इसी से उसकी सारी व्यवस्थायें निर्मित होती हैं।[1]

विचारधारा एक अभिव्यक्ति है जो एक विशोष प्रकार की व्यवस्था और विश्वास को जन्म देती है। अतः स्पष्ट है कि यह मानव व्यवहार से जुड़ी हुयी है। इसलिए विदेश नीति के निर्माण में विचारधारा का सदुपयोग करना जरूरी हो जाता है। विचार धाराओं में समानता और विरोध से उसी प्रकार के परिणाम भी परिलक्षित होते हैं। इससे लाभ और हानि दोनों ही प्राप्त होते हैं, अतः एक ऐसी विदेश नीति का चयन करना समझदारी व चातुर्य का प्रतीक है जो विभिन्न विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करके अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कर सके।

विचारधारा का उपयोग आवश्यक होने पर मुखौटे के रूप में किया जाता है, ताकि छल द्वारा भी जरूरी बल प्राप्त किया जा सके। लेकिन यह मान लेना कि यह हमेशा मक्कारी या छल पर आधारित होगी अचित नहीं है। लादी गयी विचारधारा के स्थान पर अपनायी गयी विचारधारा के द्वारा किसी राष्ट्र को ज्यादा शक्ति व महत्व प्राप्त होता है, क्योंकि इससे जनता का सहयोग बना रहता है तथा मनोबल बढ़ा रहता है। जिससे विदेश नीति के संचालन में विशेष बल मिलता है।[2]

विदेश नीति का निर्माण करने में विचारधारा का निम्नांकित महत्व है–[3]

1. अपनी नीतियों का औचित्य सिद्ध करनें में– राष्ट्र अपने हितें की पूर्ति हेतु जो विदेश नीति अपनाते हैं उसका औचित्य सिद्ध करने के लिए एक विचारधारा का विकास करते हैं। शक्ति प्राप्ति हेतु विचारधारा को प्रस्तुत करर्ना एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

2. अन्य देशों से निकटता हेतु– विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र जब यह महसूस करते हैं कि अमुक मुद्दे पर शान्ति के साथ काम लेना चाहिए तो उनमें

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

आपसी सौहाद्र पनपता है और वे एक दूसरे के निकट आते हैं।

3. दिशाहीनता से बचाव– किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति के निर्माण में विचारधारा की स्पष्टता और उसका समुचित प्रयोग करना जरूरी है। ऐसा न करने की स्थिति में कोई भी राश्ट्र दिशाहीन हो जाता है।

भारतीय विदेष नीति में हिन्दुत्ववादी विचार धारा– भारतीय जनता पार्टी ने वर्श 2014 में लोक सभा चुनाव के दौरान अपने घोषणा पत्र विदेश नीति के सम्बंध में कहा था कि, राष्ट्रों के समूह में तथा अंतराष्ट्रीय संस्थाओं में उदयीमान भारत को उसका उचित स्थान मिलना चाहिए। इसके साथ ही इस घोषण पत्र में भारतीय विदेश नीति में परिर्तन की दृष्टि से कहा गया कि विदेश नीति के लक्ष्यों, विषय वस्तु व प्रक्रिया को इस तरह से परिवर्तित और पुनर्व्यवस्थित किया जाए जिससे भारत की वैश्विक रणनैतिक संलग्नता नये परिवेश में तथा व्यापक पटल पर स्थापित हो सके। यह संलग्नता राजनैतिक कूटनीति तक ही ना सीमित हो बल्कि इसमें हमारे आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व सुरक्षा संबंधी हित भी क्षेत्रीय व वैश्विक स्तर पर शामिल हों। यह संलग्नता समानता तथा परस्पर सम्मान के सिद्धोंतों पर आधारित हो जिससे आर्थिक रूप से शक्तिशाली भारत का निर्माण हो जिसकी आवाज अंतर्राष्टीय मंचों पर सुनाई दे।[4]

इस घोषणा पत्र में यह भी साफ कहा गया है कि दक्षिण एशिया की बढ़ोतरी व विकास के लिए इस क्षेत्र में राजनैतिक स्थिरता, प्रगति तथा शांति अनिवार्य है। यह भी कहा गया कि कंग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सरकार भारत के पड़ोसी देशों के साथ स्थायी तौर पर मित्रवत तथा सहयोगात्मक सम्बंध स्थापित करने में विफल रही है। अपने परंपरागत सहयोगियों के साथ भी भारत के सम्बंध उतने सौहार्दपूर्ण नहीं रह गए हैं जितने पहले थे। भारत व इसके पड़ोसी देश एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। स्पटता की जगह अब भ्रम की स्थिति है। राष्ट्र के रूप में कूटनीतिक कौशल की इतनी भारी कमी पहले कभी महसूस नहीं की गई। भारत को आज दुलमुल राष्ट्र की तरह देखा जाता है, जबकि इसको दुनिया से आत्मविश्वास के साथ व्यवहार करना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के चरमराने से भी विदेशी मामलों में भारत का प्रभाव काफी हद तक कम हुआ है।[5]

भारत के भविष्य के सम्बंध में विचार व्यक्त करते हुए इस घोषणा पत्र में कहा गया कि हम एक शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से ओतप्रोत भारत का निर्माण करेंगे जो राष्ट्रों के बीच अपनी अधिकार पूर्ण जगह दुबारा हासिल करेगा। इस प्रयास में वसुधैव कुटुम्बकम की सदियों पुरानी परंपरा हमारा मार्गदर्शन करेगी। साथ ही साथ हमारी विदेश नीति हमारे सर्वक्षेष्ठ राष्ट्रीय हितों पर आधारित होगी। अपने हितों को साधने के लिए हम परपर साहयोग पर आधारित सहयोगियों के तानेबाने की रचना करेंगे।[6]

भारत की शांतिपूर्ण सॉट विदेश नीति के सम्बंध में बदलाव लाने के सम्बंध में इस घोषणा पत्र में कहा गया की लंबे समय से भारत अपनी सॉट पावर नीति के कारण अपनी असली क्षमता को पूर्णरूप से और व्यापक स्तर पर पहचानने में आफल रहा है। आज आवश्यकता है कि हमारी सॉट पावर के क्षेत्रों को हमारे बाहरी व्यवहार के साथ एकीकृत किया जाए, विषेशकर इसके आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं दार्शनिक आयामें पर केंद्रित करते हुए उनका पर्याप्त दोहन किया जाए।[7]

अपने घोशणा पत्र में बीजेपी ने विदेश नीति के सम्बंध में जिन मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख किया वे निम्नलिखित हैं–:[8]

1. दूर दर्शिता तथा परस्पर लाभदायक व अयोन्याश्रित सम्बंधों के सिद्धांत के द्वारा समीकरणों को ठीक किया जाएगा जो स्पष्ट हित पर आधारित है।
2. आतंकवाद तथा वैश्विक तापवृद्धि जैसे मुद्दों पर हम एक समान राय का पक्ष लेंगे।
3. बड़ी शक्तियों के हितों द्वारा निर्देशित होने की बजाए हम अपने आस–पड़ोस में तथा इससे परे देशों के साथ एवं विवके के आधार पर सक्रिय रूप से व्यपहार करेंगे।
4. अपने आस–पड़ोस में हम मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे। लेकिन जहां कहीं जरूरी हुआ वहां हम सख्त रूप से कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे।
5. हम दक्षेस और आसियान जैसे क्षेत्रीय मंचों को शक्तिशाली बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।
6. ब्रिक्स, जी 20, आईबीएसए, एससीओ तथा एसएईएम जैसे वैश्विक मंचों के साथ हम संवाद, संलग्नता तथा सहयोग जारी रखेंगे। राज्यों को कूटनीति में बृहत्तर भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अपने पारस्परिक सांस्कृतिक व व्यावसायिक हितों की मजबूती व दोहन के लिए राज्य सक्रिय रूप से विदेशों के साथ सम्बंध बना सकेंगे।
7. यह सुनिशिचत करेंगे कि दुनियॉ में हमारा संदेश स्पष्ट रूप से जाए तथा सही रूप में हमारे देश का प्रतिनिधित्व हो सके।
8. विदेशों में बसे अप्रवासी भारतीय तथा मूल के

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

निवासी वहां मौजूद पूंजी की तरह हैं जो राष्टीय हितों व मामलों की विश्वस्तर पर सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत कर सकता है। भातर ब्रांड को मजबूती देने के लिए इस विशाल जन संसाधन का उपयोग किया जाएगा।

9. अपनी जमीन से उजड़े हिंदुओं के लिए भारत सदैव प्राकृतिक गृह और यहां आश्रय लेने के लिए उनका स्वागत किया जाएगा।

2014 के चुनाव के कुछ सयम पहले नरेन्द्र मोदी नें अपने एक इन्टरव्यु में कहा था "अन्य देशों के साथ विदेशी मामलों में व्यवहार करते समय मेंरा हिंदुत्व का चेहरा बहुत उपयोगी सिद्ध होगा"। उनका यह बयान एक सख्त वैचारिक और मुखर विदेष नीति का संकेत हो सकता था, जिसने भारत को उसकी सभी भावी गतिविधियों में प्रथम बनाये रखा, फिर भी , राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की विदेश नीति के पाँच वर्षों के विश्लेषण से केवल दिशा और परिधि में बदलाव का तो पता चलता है, लेकिन वासतविक हिंदुत्व विचारधारा या तत्संबंधी किसी भी विचारधारा के सख्त अनुपालन का कोई संकेत नहीं मिलता।[9]

सन् 1923 में वी.डी. सावरकर द्वारा प्रतिपादित हिन्दुत्व शब्द, हिंदू राश्ट्र की षुद्ध विचारधारा का प्रतीक था। इसका उद्देश्य हिंदुओं में राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता स्थापित करना था। इसमें मुलमानों को हिन्दू विरोधी माना जाता था। उसके दो वर्ष के बाद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक एक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य था, हिंदुओं में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना और हिंन्दू राष्ट्र की स्थापना करना। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदू और मुसलमान दोनों बुनियादी तौर पर दो अलग–अलग परस्पर विरोधी विचारधाराएँ हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का राजनैतिक चेहरा है और नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य। 2014 के चुनावों के कुछ समय पहले प्रकाशित भारतीय जनता पाटी के 2014 के चुनावी घोषणापत्र में पार्टी ने "हिंदुत्व पर आधारित विदेश नीति" का कोई उल्लेख नहीं किया था और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को केवल तीन पृष्ठों में ही समेट लिया था। विदेश नीति को नया स्वरूप देने की इच्छा जरूर व्यक्त की गई थी और अन्य बातों के साथ–साथ भारत की सॉफट पावर को मजबूत करने या नये ढंग से गठबंधनों के अंतर्जाल की स्थापना करने की इच्छा भी प्रकट की गई थी।[10]

मोदी काल की विदेष नीति का परीक्षण

2014 –19 से द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विदेश नीति की कतिपय विशिष्ट गतिविधियों पर विस्तृत दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व अधिक सक्रिय और मुखर रहा हैं तथा उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अधिक यात्राएँ भी की हैं। उन्होंने अनेक ऐसे देशें की यात्राएँ भी कीं जहाँ दशकों से कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था। उदाहरण केलिए सन् 2015 में कनाडा, इजराइल और सुंयक्त अरब अमीरात की यात्राएँ।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पड़ोसी देशों के साथ सम्बंधों संक्षिप्त परिचय को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है:–

1. मई 2014 में अपने षपथ–ग्रहण समारोह में दक्षिण एशिया के अपने समकक्ष राष्ट्रनेताओं को आमंत्रित करके उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का मजबूत संकेत दिया था। इयके बाद सन् 2015 में मोदी ने सबसे पहले श्रीलंका की यात्रा की, मानों इस यात्रा से उन्होंने भावी गतिविधियों अर्थात भावी सहयोग और सांस्कृतिक एकता पर बल देने का सफलतापूर्वक संकेत दिया। हालॉकि उसके कुछ समय के बाद ही दोनों देशों के संबंध बिगड़ने शुरू होग गए, खास तौर पर तब जब श्रीलंका ने अपना हंबनटोटा बंदरगाह चीन को पट्टे पर देने का फैसला किया। इसके कारण इस द्वीप पर 99 साल तक चीन को मौजूद रहेने की पक्की अनुमति मिल गई।[11]

2. मालद्वीव ने भी भारत के प्रस्ताव के बावजूद, पाकिस्तान के अलावा चीन के साथ मुक्त व्यापर समझौते की पुष्टि कर दी।[12]

3. 2015 में भूकंप के बाद मोदी के शुरूआती प्रयासों और समर्थन के बावजूद नोपल ने भी चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि कर दी, जिसके कारण 2015 में नेपाल के नए संघीय संविधान के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में नाटकीय तौर पर गिरावट आई।[13]

4. इसी काल खंड में भारत के सभी नजदीकी पड़ोसी देशों को चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना में सफलतापूर्वक शामिल कर दिया गया है, जिनके संबंध में भारत की प्रतिक्रिया अभी भी स्पष्ट नहीं है।

5. पिछले पाँच वर्षों में पाकिस्तान के साथ रिश्तों में काफी उतार–चाढ़ाव आये हैं। शुरू में पाकिस्तान के साथ काफी गर्मजाशी दिखाई पड़ी जब दिसंबर 2015 में मोदी ने लाहौर की आकस्मिक यात्रा की थी, लेकिन बाद में पिछली सरकारों की तरह इस सरकार के साथ भी पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ते चले गए। खास तौर पर जब पाकिस्तान से आतंकवादीयों ने कश्मीर पर आतंकी हमले शुरू कर दिये और निंयत्रण रेखा पर लगातार और घातक झड़पें होने लगीं। सन 2019 में पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध बेहद खराब हो गए और भारत ने सर्जिकल स्टाइक करके और उसके बाद भारतीय वायु सेना द्वारा पाकिस्तान की

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

सीमा में घुसकर आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के साथ आक्रामक विदेश नीति अपना ली।[14]

6. कुल मिलकार, मोदी सरकार ने पाकिसतान को छोड़कर शेष सभी नजदीकी पड़ोसी देशों के साथ समान नीति का निरंतर अनुसारण किया है। पिछले पाँच वर्षों में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की केवल एक शिखर बैठक का ही आयोजन किया जा सका है, भारत–पाक दुशमनी के कारण इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो पा रही है।

7. चीन से संबंधित भारतीय विदेश नीति को देखें तो उसमें भी सबसे अधिक नाटकीय परिवर्तन देखे गए हैं। आरंभ में बेहद सकारात्मक सहयोग के बावजूद भी द्विपक्षीय राजनैतिक संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ। भारत–चीन सीमा–विवाद के संबंध में भी भारत की विदेश नीति बहुत मुखर रही है। लेकिन कुछ समय तक डोकलाम गतिरोध बने रहने के कारण भारत–चीन के संबंध बहुत बिगड़ गए थे। उसके बाद भारत ने बैल्ट ऐंड रोड फोरम की बैठक में भी भाग नहीं लिया और चीनी–पाकिस्तानी आर्थिक गलियारे के निर्माण को लेकर भारत ने गंभीर चिंता प्रकट की लेकिन मोदी ने चीन के साथ संबंध बनाने के लिए वूहान 2018 में राश्ट्रपति शी–जनपिंग के साथ आनौपाचारिक शिखर वार्ता की।[15]

उपरोक्त बिंदु भारत की विदेश नीति की असफलता को अधिक दर्शाते हैं, परन्तु ऐसा नहीं है कि इस काल खंड में भारतीय विदेश नीति पूरी तरह से नाकाम रही, अपितु भारत को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सफलतायें भी मिलीं हैं, जो उपरोक्त असफलताओं के प्रभाव को समाप्त कर देतीं हैं। जो कि इस प्रकार से हैं:–[16]

1. मोदी सरकार ने पिछली सरकारों की तुलना में मॉरीशस और सेशेल्स की यात्रा करके हिंद महासागर क्षेत्र में कहीं अधिक प्रगति की। इसके अलावा वे हिंद महायागर रिम संगठन के साथ अधिकाधिक गतिविधियों में भी संलग्न रहे। मोदी ने दक्षिण पूर्वेशिया की भारतीय विदेश नीति में और भी संशोधन किये, जिसकी परिणति पूर्वेन्मुखी कार्यनीति अर्थात एक्ट इस्ट पॉलिसी के रूप में हुई। यह नब्बे के दशक में अपनाई गई पूर्व की ओर देखने की नीति का ही नया संस्कण था।

2. इसके साथ ही 2016 सें अमरीका–भारत संबंध खास तौर पर उस समय और प्रगाढ़ हो गए जब दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मैमोरेंडम ऑफ ऐग्रीमेंट नामक करार हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट और सेवाओं को सुगम बनाना था। इसके बाद दोनों देषों के बीच सन् 2018 में संचार अनुकूलता और सुरक्षा समझौता (कोमकाशॉ) हुआ, जिसका उद्देश्य रक्षा प्रणालियों को उन्नत बनाना था। इसी कारण दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और भी बढ़ गई है।

3. जिस समय रूस के साथ भारत के संबंधों में गिरावट आ रही थी, उसी समय भारत ने जापान के साथ संबंधों में गर्मजोशी दिखाई दी। सन् 2014 में, जापान और भारत के बीच "विशेष रणनीतिक और वैष्विक साझेदारी" के युग की शुरूआत हुई और बुनियादी ढाँचे से संबंधित सहयोग या परमाणु ऊर्जा और प्रौद्योगिकी को क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।

4. खाड़ी देशों के साथ भारत के सम्बंध और भी सुदृढ़ हो गए और इजराइल के साथ उसके द्विपक्षीय सम्बंध पूरी तरह से सामान्य हो गए।

5. भरत की मजबूत स्थिति को दर्शाने के लिए पहला और स्पष्ट संकेत यही है कि भारत को मार्च, 2019 में इस्लामिक सहयोग संगठन के उद्घघाटन सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रिता किया गया और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के सम्बंधों ने नई ऊँचाइयों को छुआ, जिसके कारण खाड़ी के तेल के प्रमुख ग्राहक के रूप में भारत को राजनीतिक और आर्थिक लाभ मिलना आवश्यक है।

6. बहुपक्षीय परिवेश में, भारत ने क्वाड के संबंध में आगे बढ़ाने शुरू कर दिया। यह एक ऐसा समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है।

7. भारत की अपील पर सुंयक्त राष्ट्र ने विश्वव्यापी स्तर पर 21 पून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना शुरू कर दिया। वैश्विक पटल पर भारत की इस पहल के कारण उसे नई पहचान मिली और अंततः एनडीए सरकार का यह प्रमुख उद्देश्य रहा है कि विष्व भर में उन तमाम देशों को आपस में जोड़ा जाए, जहाँ प्रवासी भारतीय रहते हैं।

भारत की विदेश नीति कितनी हिन्दुत्ववादी–

भारत की विदेश नीति में हिंदुत्व पर आधारित "नई विदेश नीति" के तौर पर पूरी रतह कायाकल्प या क्रांतिकारी परिवर्तन कहीं दिखाई नहीं देता। मोदी ने भारत की विदेश नीति को भारतीय मूल्यों के साथ समन्वित करने का प्रयास जरूर किया और साझी सभ्यता और धार्मिक सम्बंधों के आधार पर दक्षिण और दक्षिण पूर्वेशिया के साथ संबंधों को बढ़ाने पर बल दिया, योग को प्रमुखता प्रदान की और खास तौर पर प्रवासी भारतीयों के साथ अपने संबंध मजबूत किये। यह भी सच है कि भारत ने महाशक्तियों के साथ–साथ अपने विस्तारित पड़ोसियों के साथ भी अपने सम्बंधों को मजबूत करना जारी रखा। पाकिस्तान और चीन के प्रति

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-I, Issues-16, YEAR- June -2020

नये आक्रामक रूख के साथ–साथ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ नई रणनीतिक साझेदारी करते हुए भारत ने नई विदेश नीति को व्यवहारवाद पर आधारित करके वस्तुतः नया संकेत दिया है।

निष्कर्ष– भारत की वर्तमान सरकार अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले तत्व के रूप में देखती है जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा सके। कभी–कभी यह राष्ट्रवाद थोड़ा उग्र और हिन्दुत्ववादी दिखाई देता है। परन्तु यह रूख भारत अपने आंतरिक मामले में ही अपना सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह विचारधारा भारत के लिए लाभ की जगह हानि अधिक पहुंचा सकती है। इस विचारधारा का लाभा प्राप्त कर वर्तमान सरकार अपनी शक्ति को बनाये रख सकती है और एक दूसरे चेहरे से चाहे वो छल वाला हो, का प्रयोग करते हुए विश्व मंच पर अपना स्थान बनाये रख सकती है। परन्तु भारत को इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके पास विदेश नीति के सम्बंध में अपनी खुद की गरिमामयी पहचान रही है। इसे किसी भी सरकार को बदलना नहीं चाहिये। हिंदुत्व पर आधारित विदेश नीति के सामने अनेक प्रकार की भू–राजनैतिक और भू–आर्थिक समस्यायें पैदा हो सकती हैं जो दीर्घकालिक हितों का प्रभावित कर सकती हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की नई विदेश नीति ने न तो नया स्वरूप धारण किया और न ही कोई नई भव्य रणनीति अपनाई। यह अवश्य है कि विदेशनीति में आर्दवादी नजरिया थोड़ा सा व्यवहारवादी हुआ है जिसकी वजह से हिंदुत्ववादी विदेश नीति की कोई आवश्यक्ता ही नहीं रह जाती तथा भारत को इस विचारधारा से बचना भी चाहिये।

REFERENCES

1. रमेश अवस्थी, विदेश नीति तथा सम्बंध, आमेगा पब्लिकेशन, 2011, पृष्ठ संख्या 1 एवं 2
2. Ibid. Page. 3
3. रमेश अवस्थी, विदेश नीति तथा सम्बंध, आमेगा पब्लिकेशन, 2011, पृष्ठ संख्या 6
4. www.bjp.org/menifesto2014 page. 61.
5. www.narendramodi.in/hi/bjp-releases-its-manifesto-for-2014-elections.
6. www.bjp.org/menifesto2014 page. 62.
7. www.narendramodi.in/hi/bjp-releases-its-manifesto-for-2014-elections.
8. www.bjp.org/menifesto2014 page. 63.
9. www.casi.sas.upenn.edu/hindi.iit/hindutva-face-foreign-policy-reflection-indian-foreign-policy-2014-19 .
10. Ibid.
11. www.khabar.ndtv.com/news/india/india-sri-lanka-sign-4-pacts-during-modi-visit.
12. www.casi.sas.upenn.edu/hindi.iit/hindutva-face-foreign-policy-reflection-indian-foreign-policy-2014-19.
13. Ibid.
14. www.m.economictimes.com/news/defence/surgica-strike-2-pakistan-jet-turned-back-due-to-size-of-iaf-formation-claim-reports.
15. www.mea.gov.in/press-releases./29853/IndiaChina_Infromal_Summit_at_Wuhan
16. www.casi.sas.upenn.edu/hindi.iit/hindutva-face-foreign-policy-reflection-indian-foreign-policy-2014-19.

*****